



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 18 दिसम्बर, 2003/27 अग्रहायण, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 18 दिसम्बर, 2003

संख्या वि०स०-विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-107/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (तृतीय संशोधन)

विधेयक, 2003 (2003 का विधेयक संख्यांक 20) जो आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाजटा,  
सचिव ।

2003 का विधेयक संख्यांक 20

**हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003 है।

संक्षिप्त नाम  
और  
प्रारम्भ।

(2) यह 30 मई, 1994 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में, “तथा उसके ऐसे अनुलग्नकों या फर्नीचर की दशा में जो उसके साथ उपयोग या उपभोग के लिए” शब्दों के स्थान पर “की दशा में सकल वार्षिक किराया, जिस पर कि ऐसा गृह या निर्माण, इसके अनुलग्नकों और किसी प्रकार के फर्नीचर सहित जो उसके साथ उपयोग या उपभोग के लिए किराए पर दिया जा सकेगा,” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 2 का  
संशोधन।

3 मूल अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रकाशन पर या इससे पूर्व किसी भी समय मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन अवधारित किया गया किसी गृह या निर्माण (बिल्डिंग) का वार्षिक मूल्य, किया गया कोई निर्धारण या की गई कर की वसूली या की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन विधिमान्यतः और विधिपूर्वक अवधारित, निर्धारित, वसूल की गई, की गई और सदैव की गई समझी जाएगी।

विधिमान्य-  
करण।

4. (1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 का एतद्-द्वारा निरसन किया जाता है।

2003 के  
अध्यादेश  
संख्यांक 6  
का निरसन  
और व्या-  
वृत्तियां।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 2 की उप-धारा (1) में अभिव्यक्ति (पद) "वार्षिक मूल्य" की परिभाषा उपबन्धित है। दाण्डिक रिट याचिका संख्या 125/03 की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में कुछ त्रुटियां इंगित की हैं और इन त्रुटियों को तुरन्त दूर करने के लिए निदेश दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निदेश की अनुपालना करने के लिए, इस खण्ड के उपबन्धों को और पारदर्शी (अधिक स्पष्ट) करने के लिए उपरोक्त खण्ड (ख) में तुरन्त संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था। इसलिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

2. क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में तुरन्त संशोधन करना आवश्यक हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का अध्यादेश संख्यांक 6) 26 जुलाई, 2003 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे 26 जुलाई, 2003 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

3. यह विधेयक उक्त अध्यादेश को, बिना किसी उपांतरण के, प्रतिस्थापित करने के लिए है।

**वीरभद्र सिंह,**  
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख . . . . . दिसम्बर, 2003.

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

**AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT**

**Bill No. 20 of 2003.**

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (THIRD AMENDMENT)  
BILL, 2003**

**(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)**

**A**

**BILL**

*further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows:--

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Third Amendment) Act, 2003.

Short title  
and comm-  
encement.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on the 30th day of May, 1994.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), in clause (b), for the words "together with its appurtenances or any furniture that may be let for use and", the words and sign "the gross annual rent at which such house or building together with its appurtenances and any furniture that may be let for use or" shall be substituted.

Amendment  
of section  
2.

3. Notwithstanding anything to the contrary contained in the principal Act, any annual value of house or building determined, any assessment or recovery of tax made or any action taken or anything done under the provisions of the principal Act, at any time on or before the publication of the Himachal Pradesh Municipal (Third Amendment) Act, 2003 shall and shall always be deemed to have been validly and lawfully determined, assessed, recovered, taken or done under the provisions of the principal Act as amended by this Act.

Validation.

4. (1) The Himachal Pradesh Municipal (Third Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

Repeal of  
Ordinance  
No. 6 of  
2003 and  
savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. Sub-section (1) of section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 provides for definition of the term "annual value". The Hon'ble High Court while hearing CWP No. 125/03, pointed out that there is a discrepancy in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Act *ibid* and directed to rectify the omission immediately. In order to comply with the direction of the Hon'ble High Court, the said clause (b) was to be amended immediately to make the provisions of this clause crystal clear. Thus it was decided to amend clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Act *ibid*.

2. Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in Session and the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Municipal (Third Amendment) Ordinance, 2003 (Ordinance No. 6 of 2003) on 26th day of July, 2003 and same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on the 26th day of July, 2003. Now the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

3. The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

VIRBHADRA SINGH,  
Chief Minister.

SHIMLA :

Dated, ..... December, 2003.

## FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-